



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3(i)

PART II—Section 3(i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 573]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 14, 2018/श्रावण 23, 1940

No. 573]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 14, 2018/SHRAVANA 23, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 2018

संख्या 73 /2018- सीमाशुल्क (गै.टै.)

सा.का.नि.779(अ).—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 157 के उपवाक्य (घ) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, उक्त अधिनियम की धारा 18 के साथ और धारा 158 की उपधारा (2) के उपवाक्य (ii) के साथ पठित, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथा: -

- संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ.**— (1) इन विनियमों को सीमाशुल्क (अनंतिम आंकलन को अंतिम रूप देना) विनियम, 2018 कहा जाएगा।
(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- परिभाषाएँ.**— (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अभिप्रेत ना हो--
(क) 'अधिनियम' से अभिप्राय सीमाशुल्क अधिनियम, (का 52 1962) 1962 से है;
(ख) 'बोर्ड' से अभिप्राय केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड से है;
(ग) 'यथोचित अधिकारी' से अभिप्राय उपायुक्त या सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क से है;
(2) जिन शब्दों और अभिव्यक्तियों का यहाँ प्रयोग हुआ है लेकिन उनको इस विनियम में परिभाषित नहीं किया गया है लेकिन इस अधिनियम में परिभाषित किया गया है तो उनका वही अभिप्राय होगा जो उक्त अधिनियम में इनके लिए क्रमशः दिया गया हो।
- प्रयोज्यता.**— ये विनियम उन अनंतिम आंकलनों पर लागू होंगे जिनके लिए आदेश इन विनियमों के लागू होने के दिन एवं बाद में दिया गया हो।

4. अनंतिम आंकलनों को अंतिम रूप देने के उद्देश्यार्थ कागजात या जानकारी प्रस्तुत करने की समय सीमा और तरीका. —

- (1) जहाँ कि अनंतिम आंकलन के लिए यथोचित अधिकारी ने इस कारण से आदेश दिया हो कि, -
 - (क) आयातकर्ता या निर्यातकर्ता ने आवश्यक कागजात या जानकारी उपलब्ध नहीं करायी है; या
 - (ख) यथोचित अधिकारी आयातकर्ता या निर्यातकर्ता से किसी अतिरिक्त कागजात या जानकारी को प्रस्तुत किए जाने की अपेक्षा रखता है;
 तो ऐसी जानकारी या कागजातों को आयातकर्ता या निर्यातकर्ता के द्वारा ऐसे आदेश की तारीख से अथवा यथोचित अधिकारी द्वारा ऐसी मांग किए जाने की तारीख से एक महीने के भीतर, उपलब्ध कराया जाना होगा।
- (2) यथोचित अधिकारी ऐसे अनंतिम आंकलन के आदेश की तारीख से 15 दिन के भीतर आयातकर्ता या निर्यातकर्ता को लिखित रूप में उस जानकारी का विशेष व्योरा देने के लिए सूचित करेगा जिसको कि प्रस्तुत किया जाना हो या जो कागजात प्रस्तुत किया जाना हो।
- (3) यदि उपनियम (1) में निर्धारित अवधि के भीतर उक्त कागजात या जानकारी नहीं उपलब्ध कराई जा पाती है तो यथोचित अधिकारी, आवश्यक कारण को लिखित रूप में दर्ज करते हुए, अपनी ओर से या आयातकर्ता या निर्यातकर्ता के अनुरोध पर इस अवधि को अधिकतम 3 माह की और अवधि दे सकता है।
- (4) उक्त कागजात या जानकारी जिसे कि आयातकर्ता या निर्यातकर्ता द्वारा उपलब्ध कराया जाना है या जो यथोचित अधिकारी के द्वारा अपेक्षित है निर्धारित अवधि के भीतर उपलब्ध नहीं कराई जा पाती है तो, अपर आयुक्त/ संयुक्त आयुक्त, सीमाशुल्क, यथा संदर्भित समयावधि को अगले 3 महीने के लिए और भी बढ़ा सकता है।
- (5) यदि आयातकर्ता या निर्यातकर्ता के द्वारा जमा किए जाने वाले कागजात या दी जाने वाली सूचना या यथोचित अधिकारी द्वारा अपेक्षित कागजात या जानकारी को उप विनियम (4) के अंतर्गत बढ़ायी गयी समय सीमा के भीतर भी जमा नहीं किया जा पाता है तो सीमाशुल्क आयुक्त इस समयावधि को जितना उचित समझे उतना और भी आगे बढ़ा सकता है।
- (6) कागजात या जानकारी जिसे कि आयातकर्ता या निर्यातकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित हो या जिसे यथोचित अधिकारी द्वारा मांगा गया हो, को एक बार में प्रस्तुत कर सकता है।
- (7) आयातकर्ता या निर्यातकर्ता या उसका कोई प्राधिकृत प्रतिनिधि या कस्टम्स ब्रोकर यथोचित अधिकारी को लिखित में यह सूचना देगा कि उसने सभी कागजात या जानकारी, जिसको की जमा किया जाना अपेक्षित था या जिसकी मांग की गयी थी, को प्रस्तुत कर दिया है।
- (8) इन विनियमों के प्रयोजन के लिए, प्रत्येक बिल ऑफ एन्ट्री या शिपिंग बिल, जैसी भी स्थिति हो, जिसको कि अनंतिम रूप से आंकलित किया गया हो, के बारे में यह माना जाएगा कि यह अनंतिम आंकलन का अलग मामला है।

5. अनंतिम आंकलन को अंतिम रूप देने की समय सीमा.- (1) यथोचित अधिकारी निम्नलिखित की प्राप्ति की तारीख से दो महीने भीतर अनंतिम आंकलन को अंतिम रूप दे देगा:

- (क) विनियम 4 के उप विनियम (7) के अंतर्गत आयातकर्ता या निर्यातकर्ता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि या कस्टम्स ब्रोकर से प्राप्त होने वाली सूचना; या
- (ख) रासायनिक या अन्य परीक्षण रिपोर्ट, जहाँ कि इन्ही के कारण अनंतिम आंकलन का आदेश दिया गया हो; या
- (ग) किसी जांच या पड़ताल या सत्यापन रिपोर्ट, जहाँ कि इन्ही के कारण अनंतिम आंकलन का आदेश दिया गया हो।

बशर्ते कि जहाँ कि कागजात या सूचना जिसे आयातकर्ता या निर्यातकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है या जिसके लिए यथोचित अधिकारी ने मांग की है, को कई बार में जमा किया जाता है तो वहाँ दो महीने की अवधि की गणना उपर्युक्त उपवाक्य (क) में संदर्भित अंतिम सूचना की प्राप्त होने की तारीख से की जाएगी।

बशर्ते और भी कि जहाँ कागजात या सूचना जो कि आयातकर्ता या निर्यातकर्ता द्वारा, जैसी भी स्थिति हो, प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है या जिसके लिए यथोचित अधिकारी ने मांग की है, को जमा नहीं किया जाता है या उसे आंशिक रूप से जमा किया जाता है और विनियम 4 के उप विनियम (3), (4) या (5), जैसी भी स्थिति हो, में कोई भी समयावधि बढ़ाई नहीं गयी है तो यथोचित अधिकारी उक्त कागजात या जानकारी को जमा किए जाने के लिए दिये गए समय के समाप्त होने की तारीख से दो महीने के भीतर अनंतिम आंकलन को अंतिम रूप देने की कार्यवाही को पूरा करेगा।

(2) यदि यथोचित अधिकारी उपर्युक्त उप विनियम (1) में यथा विनिर्दिष्ट दो महीने की अवधि के भीतर अनंतिम आंकलन को अंतिम रूप नहीं दे पाता है तो संबन्धित आयुक्त, सीमाशुल्क लिखित में कारण को बताते हुए, तीन महीने की अवधि और दे सकता है।

(3) यह विनियम ऐसे अनंतिम आंकलनों के मामलों पर लागू नहीं होगा जिसको कि विचाराधीन रखने के लिए बोर्ड ने निर्देश दिया हो।

6. अनंतिम आंकलन को अंतिम रूप देने का तरीका.- (1) अनंतिम आंकलन को अंतिम रूप उक्त अधिनियम की धारा 18 में यथा अपेक्षित तरीके से दिया जाएगा।

बशर्ते कि यदि अनंतिम आंकलन के समय या धारा 18 की उपधारा (2) के उपवाक्य (क) के तहत समायोजन के बाद भुगतान की गयी राशि अंतिम रूप से आंकलित या पुनः आंकलित राशि, जैसी भी स्थिति हो, से कम है और आयातकर्ता या निर्यातकर्ता ने “डेफ़िसिएन्सी” का भुगतान नहीं किया है तो इस प्रकार रह गयी “डेफ़िसिएन्सी” को अनंतिम आंकलन के समय प्राप्त की गयी प्रतिभूति, यदि कोई हो, में से, आयातकर्ता या निर्यातकर्ता को इस बात की सूचना देते हुए समायोजित कर लिया जाएगा।

बशर्ते और भी कि इस प्रकार समायोजित की गयी या भुगतान की गयी राशि अंतिम रूप से आंकलित या पुनः आंकलित राशि, जैसी भी स्थिति हो, से फिर भी कम है, तो माल का आयातकर्ता या निर्यातकर्ता धारा 18 के प्रावधानों के अनुसार कम रह गयी इस राशि का भुगतान करेगा।

(2) अनंतिम आंकलन के समय प्रतिभूति के साथ साथ या उसके बिना जमा किए गए बंधपत्र को अनंतिम आंकलन को अंतिम रूप दिए जाने पर रद्द कर दिया जाएगा और प्रतिभूति को वापिस कर दिया जाएगा बशर्ते कि कोई देय बकाया ना हो।

(3) जहाँ कि अंतिम आंकलन और अनंतिम आंकलन में विरोधाभास हो वहाँ यथोचित अधिकारी नैषर्गिक न्याय के सिद्धान्त का अनुपालन करते हुए सुस्पष्ट आदेश देगा।

(4) जहाँ कि अंतिम आंकलन में अनंतिम आंकलन की पुष्टि हो जाती है वहाँ यथोचित अधिकारी आयातकर्ता या निर्यातकर्ता से लिखित में ऐसे अंतिम आंकलन की स्वीकृति सुनिश्चित करने के पश्चात इसको अंतिम रूप देगा और आयातकर्ता या निर्यातकर्ता को लिखित रूप में ऐसी तारीख के बारे में सूचित कर देगा।

(5) जहाँ कि बिल ऑफ़ एंट्री या शिपिंग बिल को कस्टम्स औटोमेटेड सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किया जाता है और इसके अनंतिम आंकलन के लिए आदेश दिया जाता है तो यथोचित अधिकारी इन विनियमों को विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के तहत अंतिम रूप दिये जाने के पश्चात इसको सिस्टम में भी इसको अंतिम रूप देगा।

7. दंड.- यदि कोई आयातकर्ता या निर्यातकर्ता या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि या कस्टम्स ब्रोकर इन विनियमों के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है या ऐसे उल्लंघन के लिए उकसाता है या इन विनियमों के किसी प्रावधान का अनुपालन नहीं कर पाता है, तो वह पचास हजार रुपए तक के दंड का भागी होगा।

[फा. स. 450/76/2018- सीमाशुल्क IV]

जुबैर रियाज़, निदेशक (सीमाशुल्क)

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)****NOTIFICATION**New Delhi, the 14th August, 2018**No.73/2018-Customs(N.T.)**

G.S.R.779(E).—In exercise of the powers conferred by clause (d) of section 157 read with section 18 and clause (ii) of sub-section (2) of section 158 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes and Customs hereby makes the following regulations, namely:

3. **Short title and commencement.** – (1) These regulations may be called the Customs (Finalisation of Provisional Assessment) Regulations, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

4. **Definitions.** – (1) In these regulations, unless the context otherwise requires--

(a) 'Act' means the Customs Act, 1962 (52 of 1962);

(b) 'Board' means the Central Board of Indirect Taxes and Customs;

(c) 'proper officer' means Deputy Commissioner or the Assistant Commissioner of Customs;

(2) The words and expressions used herein and not defined in these regulations but defined in the Act shall have the same meanings respectively assigned to them in the said Act.

3. **Application.** – These regulations shall apply to the provisional assessments ordered on and after the enforcement of these regulations.

4. **Time-limit and manner for submission of documents or information for the purpose of finalisation of provisional assessment.** – (1) Where a provisional assessment is ordered by the proper officer for the reasons that, -

(a) the necessary documents have not been produced or information has not been furnished by the importer or the exporter; or

(b) the proper officer requires the importer or the exporter to produce any additional documents or information,

then such information or documents shall be made available by the importer or the exporter within one month from the date of such order of provisional assessment or the date of such requisition by the proper officer, as the case may be.

(2) The proper officer shall within fifteen days from the date of such order of provisional assessment, inform the importer or the exporter, in writing, the specific details of the information to be furnished or the documents to be produced.

(3) The proper officer may, for reasons to be recorded in writing, allow a further period not exceeding three months, on his own or at the request of the importer or the exporter, in case the documents or information are not made available within the time period specified in sub-regulation (1).

(4) The Additional Commissioner or Joint Commissioner of Customs, may further extend the time period referred for another three months, in case the documents or the information required to be submitted by the importer or

the exporter or requisitioned by the proper officer have not been made available within the period as allowed above by the proper officer.

- (5) The Commissioner of Customs, may extend the time period further as deemed fit, in case the documents or the information required to be submitted by the importer or the exporter or requisitioned by the proper officer have not been made available even after the extension of time under sub-regulation (4).
 - (6) The documents or information required to be furnished by the importer or the exporter or requisitioned by the proper officer may be submitted in one instance.
 - (7) The importer or the exporter or his authorised representative or Customs Broker shall inform the proper officer in writing that he has submitted all the documents or information to be furnished or requisitioned.
 - (8) For the purpose of these regulations, each Bill of Entry or Shipping Bill, as the case may be, that has been assessed provisionally shall be treated as a separate case of provisional assessment.
5. **Time-limit for finalisation of provisional assessment.** – (1) The proper officer shall finalise the provisional assessment within two months of receipt of:
- (a) an intimation from the importer or the exporter or his authorised representative or Customs Broker under sub-regulation (7) of regulation 4; or
 - (b) a chemical or other test report, where the provisional assessment was ordered for that reason; or
 - (c) an enquiry or investigation or verification report, where the provisional assessment was ordered for that reason.

Provided that where the documents or information required to be furnished by the importer or the exporter or requisitioned by the proper officer are made available intermittently, the time period of two months shall be reckoned from the date of last intimation referred to in clause (a) above,;

Provided further that where the documents or information required to be furnished by the importer or exporter, as the case may be, or requisitioned by the proper officer are not made available or made partly available and no further extension of time has been allowed under sub-regulations (3), (4) or (5) of regulation 4, as the case may be, the proper officer shall proceed to finalise the provisional assessment within two months of the expiry of the time allowed for submission of the said documents or information.

- (2) The Commissioner of Customs concerned may allow, for reasons to be recorded in writing, a further time period of three months in case the proper officer is not able to finalise the provisional assessment within the period of two months as specified in sub-regulation (1) above.
 - (3) This regulation shall not apply to such cases of provisional assessments, where Board has issued directions to keep that pending.
6. **Manner of finalisation of provisional assessment.** – (1) The provisional assessment shall be finalised as per the provisions of section 18 of the Act.

Provided that if the amount so paid at the time of provisional assessment or after adjustment under clause (a) to sub-section (2) of section 18 of the Act, falls short of the duty finally assessed or re-assessed, as the case may be, and the importer or the exporter has not paid the deficiency, the shortfall shall be adjusted from the security, if any, obtained at the time of provisional assessment, under intimation to the importer or the exporter,;

Provided further that, if the amount so adjusted or paid falls short of the duty finally assessed or re-assessed, as the case may be, the importer or exporter of the goods shall pay the shortfall in terms of the provisions of section 18.

(2) The Bond executed at the time of provisional assessment with security, if any, shall be cancelled after finalisation of provisional assessment and the security shall also be returned, if there are no pending dues.

(3) Where the final assessment is contrary to the provisional assessment, the proper officer shall pass a speaking order following principles of natural justice.

(4) Where the final assessment confirms the provisional assessment, the proper officer shall finalise the same after ascertaining the acceptance of such finalisation from the importer or the exporter on record and inform the importer or exporter in writing of the date of such finalisation.

(5) Where a Bill of Entry or Shipping Bill is presented electronically on the Customs Automated system and is ordered to be provisionally assessed, the proper officer shall finalise the provisional assessment on the system also consequent to the procedure prescribed in these regulations.

7. **Penalty.** - If any importer or exporter or his authorised representative or Customs Broker contravenes any provision of these regulations or abets such contravention, or fails to comply with any provision of these regulations, he shall be liable to a penalty which may extend to fifty thousand rupees.

[F. No.450/76/2018-CusIV]
ZUBAIR RIAZ, Director (Customs)